Reporters Required!
For
Delhi, Haryana, UP,
Ludhiana, Shimla,
Bihar, Jammu, Jaipur
Amritsar, Bathinda,
Call/WhatsApp:
+91-9157875000
+91-9815619715
Email:
azadvaani65@gmail.com

Monthly Hindi/English Newspaper

Published from SAS Nagar (Mohali)

Azad वाणी

NEWS • VIEWS • ANALYSIS

RNI No.
PBBIL/26/A0779

ट्राइसिटी में ED का बड़ा एक्शन: करोड़ों के रियल एस्टेट खेल का पर्दाफाश, बिल्डरों में मचा हड़कंप

चंडीगढ़, 28 मई : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने किशोरियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने पंजाब के सभी 23 जिलों के सरकारी हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में "मासिक धर्म स्वच्छता पाठ्यक्रम" लागू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का पहला सत्र 29 मई से शुरू होगा।

इस पहल से राज्य के 3,600 से अधिक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 10 तक की करीब 3.4 लाख छात्राओं को लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़े मिथकों, झिझक और सामाजिक कलंक को खत्म कर छात्राओं को सही स्वास्थ्य जानकारी, आत्मविश्वास और सम्मान प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय संस्था WASH United के सहयोग से शुरू किया गया है। पाठ्यक्रम पंजाबी भाषा में तैयार किया गया है ताकि छात्राएं इसे आसानी से समझ सकें। इसमें 'रूबी' नामक 10 वर्षीय बच्ची की कहानी के माध्यम से इंटरैक्टिव सत्र, चर्चा और गतिविधियां करवाई जाएंगी। छात्राओं को शरीर में होने वाले बदलाव, स्वच्छता, आत्म-देखभाल और आत्मविश्वास के बारे में जागरूक किया जाएगा।

कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए पंजाब सरकार ने लगभग 7,200 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया है। पहले 100 राज्य स्तरीय संसाधन व्यक्तियों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया, जिसके बाद जिला स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

सरकार के अनुसार, पहले 100 से अधिक स्कूलों में किए गए पायलट प्रोजेक्ट में 45 हजार से ज्यादा छात्राओं ने हिस्सा लिया था। 97 प्रतिशत शिक्षकों ने पाठ्यक्रम को प्रभावी बताया, जबकि 94 प्रतिशत ने इसे पूरे पंजाब में लागू करने की सिफारिश की।

शिक्षकों और छात्राओं ने भी कार्यक्रम को सकारात्मक बताया। उनका कहना है कि इससे मासिक धर्म को लेकर खुलकर बातचीत का माहौल बना है और लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ा है।

पंजाब सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल छात्राओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि उन्हें सम्मानजनक और जागरूक वातावरण भी प्रदान करेगी।

चंडीगढ़ में 24x7 कारोबार नीति को बढ़ावा, 179 प्रतिष्ठान रातभर संचालन के लिए पंजीकृत

चंडीगढ़ प्रशासन की 24x7 कारोबार नीति को शहर में लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले लगभग दो वर्षों के दौरान शहर के 179 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने पूरी रात संचालन के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें सबसे अधिक संख्या फूड आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे और सुविधा स्टोर्स की बताई जा रही है। प्रशासन का मानना है कि इस नीति से चंडीगढ़ धीरे-धीरे एक आधुनिक "नाइट इकॉनमी" मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जिससे व्यापार, रोजगार और नागरिक सुविधाओं को नया विस्तार मिलेगा।

चंडीगढ़ प्रशासन ने 24x7 कारोबार नीति को शहर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू किया था। इसके तहत निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रातभर खुला रखने की अनुमति दी जाती है। प्रशासन का कहना है कि इस पहल से न केवल

व्यापारियों को फायदा हो रहा है बल्कि रात के समय काम करने वाले कर्मचारियों, यात्रियों और छात्रों को भी काफी सुविधा मिल रही है।

आंकड़ों के अनुसार देर रात तक सबसे अधिक सक्रियता खाने-पीने के कारोबार में देखी जा रही है। शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों में कैफे, ढाबे, बेकरी और फूड जॉइंट्स रातभर सेवाएं दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इससे बिक्री में बढ़ोतरी हुई है और नए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। वहीं युवाओं और कामकाजी लोगों के बीच भी यह सुविधा लोकप्रिय हो रही है।

हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रातभर संचालन करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को सुरक्षा, पार्किंग, शोर नियंत्रण और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। पुलिस और प्रशासनिक टीमें समय-समय पर निरीक्षण भी कर रही हैं ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नीति सफल रहती है तो आने वाले समय में चंडीगढ़ उत्तर भारत के प्रमुख "24x7 एक्टिव सिटी" मॉडल के रूप में उभर सकता है। प्रशासन भी भविष्य में इस नीति के दायरे को और विस्तारित करने की योजना पर काम कर रहा है।

2030 तक 32% वन क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य

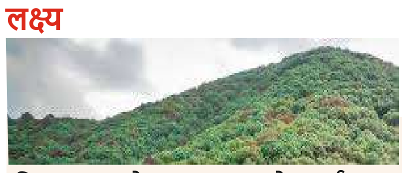

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए 'मिशन-32 प्रतिशत' अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत वर्ष 2030 तक राज्य के वन क्षेत्र को मौजूदा 29.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह अभियान शुरू किया गया है।

वन विभाग द्वारा राज्यभर में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों, पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय लोगों को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है ताकि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जा सके। सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जैव विविधता को सुरक्षित रखने पर भी विशेष ध्यान दे रही है।

अधिकारियों के अनुसार, आने वाले वर्षों में लाखों पौधे लगाए जाएंगे और वन क्षेत्रों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा और पर्यटन व कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा।

हिमाचल में सरकारी नौकरियों के लिए 'एंटी-चिट्टा टेस्ट' अनिवार्य

हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि अब सरकारी नौकरियों में चयनित होने वाले उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति से पहले "एंटी-चिट्टा टेस्ट" यानी ड्रग टेस्ट अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि युवाओं को नशे की लत से बचाने और प्रशासनिक व्यवस्था को स्वच्छ एवं जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और आने वाले समय में जागरूकता अभियान भी तेज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों का असर युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है, इसलिए सरकार इस समस्या से सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार के अनुसार, ड्रग टेस्ट की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग और संबंधित एजेंसियों की निगरानी में करवाई जाएगी।

मोहाली नगर निगम चुनावों में बढ़ी सियासी गर्मी, आज होगी मतगणना

मोहाली में नगर निगम और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्माया हुआ है। जिले की सात स्थानीय निकाय संस्थाओं में हुए मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की नजरें 29 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई हैं। इस बार मोहाली, जीरकपुर, डेराबस्सी, कुराली, लालड़, बनूड़ और नयागांव समेत कई क्षेत्रों में मुकाबला बेहद दिलचस्प और हाई-प्रोफाइल माना जा रहा है। चुनाव मैदान में कुल 695 उम्मीदवार उतरे थे, जबकि लगभग 4.8 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

चुनाव के दौरान भीषण गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। हालांकि दोपहर के समय तापमान बढ़ने से मतदान की रफ्तार कुछ धीमी हुई। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरे जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। करीब 498 मतदान केंद्रों पर पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। कई संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई।

इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान विकास, सफाई व्यवस्था, पानी, ट्रैफिक और अवैध निर्माण जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद विपक्षी दलों ने प्रशासन और पुलिस मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने कुछ क्षेत्रों में धांधली तथा मतदाताओं पर दबाव बनाने की शिकायतें दर्ज करवाई हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक बयानबाजी बताया है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस बार मोहाली नगर निगम चुनाव केवल स्थानीय निकाय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें आने वाले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। खासतौर पर मेयर पद को लेकर कई बड़े राजनीतिक परिवारों और नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। परिणाम यह तय करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में किस दल का प्रभाव सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है।

मतगणना को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

Advertisement

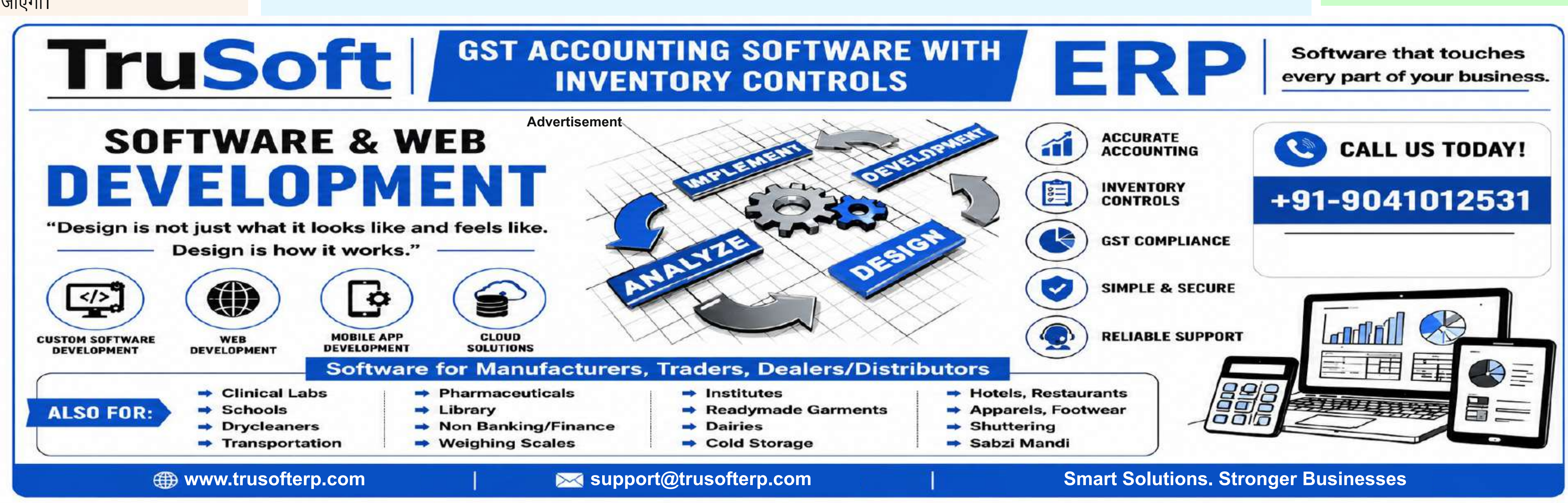

herbegy™
Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.

PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:
727-515-0015